

**MR. DEPUTY-SPEAKER**

"That leave be granted to introduce a Bill to repeal the Maintenance of Internal Security Act, 1971 and the Defence of India Act, 1971."

*The motion was adopted.*

**SHRI SOMNATH CHATTERJEE:** I introduce the Bill.

15.42 hrs.

**CONSTITUTION (AMENDMENT)  
BILL**

(Amendment of article 352) by  
Shri Hari Vishnu Kamath—contd.

**MR. DEPUTY SPEAKER:** Now, we come to further consideration of Shri Kamath's Bill.

**SHRI P. K. DEO (Kalahandi):** Sir, Shri Kamath is now out of India on official duty. And so, it will not be fair to adjourn the debate on that Bill. But, the Bill could be discussed in his absence. He will continue to have the right to reply.

Secondly, two hours were allotted for the discussion of this Bill and the time has been fully consumed. So, my motion in this regard, is as follows:

"That the debate on the Constitution Bill (Amendment of article 352) be adjourned."

**SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar):** I do not see any reason why he wants to adjourn this discussion on this Bill. Has Shri Kamath written to you any letter about this Bill?

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** No.

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:** If he has not written, I do not see any reason for adjourning the debate on the Bill unnecessarily.

**SHRI C. K. CHANDRAPAN (Cannanore):** If we continue the discussion, he will get priority. But, if it is adjourned, he may not get it.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Mr. Gupta, the position is this. We have

allowed two hours for this and these two hours have already been consumed. So, either we have to extend the time for which another motion is to be put or we have to adjourn it.

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:** The time should be extended.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Then, the mover is not here; he will not be able to listen to it.

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:** He has already explained the position while moving this Bill. The Minister is here. If we adjourn that to-day then, I am not sure whether the Bill get the priority automatically or not.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** It has to be balloted again.

**SHRI SAMAR GUHA (Contai):** If it is balloted, where is the surety that he will get the priority?

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** He is bound to get the priority.

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:** We do not want to adjourn this. We want that the time should be extended by another two hours.

**SHRI SAMAR GUHA:** Is it possible to get the priority?

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** That is for the House to decide.

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:** You kindly take the leave of the House.

**SHRI SAMAR GUHA:** Before that, I want to seek some clarification on this. Is there a possibility of his getting the priority in the ballot?

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Once it is balloted, then it may be given the priority. What do you propose to do? Do you want the time to be extended?

**SHRI P. K. DEO:** Mr. Kamath should get his right of reply.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Would the Minister like to intervene?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NAR-SINGH YADAV):** I am ready to intervene.

**MR. DEPUTY SPEAKER:** Then, we can extend the time by another one hour so that the Members may speak on the Bill. Even if we adjourn the debate at this stage, the position remains the same. Don't you see the point, Mr. Gupta?

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:** At least when the the Minister replies. If the Member concerned is not here, then you vote it. That is all.

**MR. DEPUTY SPEAKER:** Only another motion will have to be moved without his reply.

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:** It is all right. Sir, it is an important Bill and we must know the views of the Government.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा)  
उपाध्यक्ष जी, जो बूबर आफ बि बिल है वे आज यहा पर उपस्थित नहीं हैं। उन को भी जबाब देने का अधिकार है। इस लिए इसको स्थगित करिये।

श्री कंवर लाल गुप्त - बैलेट मे यह खत्म हो जाएगा और यह एक इम्पोर्टेंट बिल है।

**MR. DEPUTY SPEAKER:** So, the discussion can go on for one more hour and then the Minister would take the opportunity of replying when Mr. Kamath is here. So, we are extending the time by one hour. The House has to take a decision.

**SHRI P. K. DEO:** I withdraw the Motion moved by me.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** So, we extend the debate by one hour and at the end of one hour Mr. Deo's Bill will be taken up.

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष जी, मैं कामत जी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सुन्दर बिल और ऐसे बिज़ की भाज आवश्यकता थी, सदन के सामने पेश किया। इमर्जेन्सी का प्रावधान कांस्टीट्यूशन मे प्रारंभ से है।

15.45 hrs.

सभापति जी, आप को याद होगा कि जब इमर्जेन्सी का प्रावधान बनाया गया था, उस समय कामत साहब ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि यह इमर्जेन्सी किसी समय भी मिसयूज हो सकती है। उस समय डा० अम्बेदकर ने कहा था कि हमें यह धारा करनी चाहिए कि ऐसा कोई अवसर नहीं आएगा जब इमर्जेन्सी का दुरुपयोग होगा और 1950 से ले कर 1975 तक, मैं यह कह सकता हूँ कि कोई ऐसा अवसर नहीं आया कि 25 साल में सरकार ने इस इमर्जेन्सी का दुरुपयोग किया हो लेकिन 1975 के अन्दर 19, 20 महीने जो स्थिति रही वह ऐसी भयानक रही कि शायद वैधानिक तरीके से विधान को खत्म करने की कोशिश की गई।

The Constitution was destroyed by constitutional means.

उस समय जो सब से बड़ा भाग रहा, वह इमर्जेन्सी के क्लॉज का रहा कि इमर्जेन्सी डेक्लेयर कर दी गई और उस को चेलेज भी नहीं किया जा सकता था। इस इमर्जेन्सी में जो पूरी तानाशाही की पावर्स हैं, वे पूरी की पूरी प्रधान मंत्री जी ने अपने हाथ में ले ली। आप ने शाहू कमीशन के बारे में पढ़ा होगा और समाचार-पत्रों में

[श्री कवर लाल गुप्त]

एमजेंसी के समय के बहुत से तथ्य आ रहे हैं। उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन 19 महीना में जिस तरह का जीवन इस देश में रहा, वह किसी भी सिविलाइज्ड और डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इसके बारे में दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ी है। इन चीजों को सामने रखते हुए कि 19 महीने तक जो इस देश में तानाशाही का नाच होता रहा, जिसमें लाखों का जो फुटामेंटल राइट है उसको भी खत्म कर दिया गया था, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी और आज जो है उसका एक घंटे के बाद क्या होगा, कहा नहीं जा सकता था, यह बिल बहुत सामयिक है। 19 महीने जो देश में एक नई क्रांति आई है। जनता ने एक नया मोट लिया और भाति-पूर्वक क्रांति आई। इसलिए यह जरूरी हो गया कि इस चीज पर दुबारा विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, एक तो सवाल यह आता है कि क्या एमजेंसी का प्रावधान संविधान में हो या न हो। कुछ लोग ऐसा सोचने वाले भी हैं कि एमजेंसी का घाटिकल संविधान से बिल्कुल हटा दिया जाए। लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। हालांकि मैं एमजेंसी हलालत का शुक्लधोगी हूँ, 19 महीने जेन में रहा हूँ लेकिन मैं यह समझता हूँ कि एमजेंसी के घाटिकल का संविधान में निकालना उचित नहीं होगा। हमारा देश बहुत बड़ा है। इसमें कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब कि एमजेंसी लगाना जरूरी हो जाए। लेकिन जो पब्लिक डिसऑर्डर या कोई और शब्द हैं, मेरे ख्याल में उनको इस घाटिकल से हटा देना चाहिए। केवल दो

कारणों से एमजेंसी लगनी चाहिए। एक तो जब बाहर का एग्जेंट हो। जब कोई विदेशी हमारे देश पर आक्रमण कर दे तब एमजेंसी लगनी चाहिए। दूसरे जब देश के अन्दर ही आर्ट्स रिबेलियन हो जाए तो एमजेंसी लगानी चाहिए। इन के अतिरिक्त पब्लिक डिसऑर्डर या कोई और जो शब्द इस एमजेंसी के घाटिकल में हैं उनको हटा देना चाहिए। इतना एमडमट इस घाटिकल में होना चाहिए।

अब सवाल यह आता है कि जब आर्ट्स रिबेलियन या एक्सटर्नल एग्जेंट होता है तो क्या एक प्रदेश से या सारे देश में एमजेंसी लगायी जाए। मान लीजिए किसी एक प्रदेश के उपर जैसे पंजाब या पश्चिम बंगाल के उपर विदेशी आक्रमण होता है तो यह आक्रमण सारे देश पर माना जाना चाहिए और सारे देश में ही एमजेंसी लगायी जानी चाहिए। लेकिन जब आर्ट्स रिबेलियन होता है तो वह किसी प्रदेश या प्रदेशों तक ही सीमित होता है, उस सूत्र में सारे देश में एमजेंसी लगाना जरूरी नहीं है, केवल उन प्रदेशों या प्रदेश में ही एमजेंसी लगाना उचित होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस एमजेंसी के घाटिकल का मोडिफाई किया जाए, सरल किया जाए। फारन एग्जेंट के समय सारे देश में और आर्ट्स रिबेलियन के समय केवल उसी प्रदेश में जिसमें यह हो, एमजेंसी लगाने की व्यवस्था संविधान में हो। अन्यथा एमजेंसी लगाने की व्यवस्था को संविधान से समाप्त किया जाना चाहिए। इस एमजेंसी के प्रस्ताव को यह सदन एक मत से पास करे।

अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने उस समय के संविधान की व्यवस्था को भी तोड़ा। जब देश में इंदिराजी

ने एमजेंसी लगायी उस समय तक उस समय की कैबिनेट ने एमजेंसी को प्रस्ताव को पास नहीं किया था। कैबिनेट ने यह बात पास नहीं की थी कि देश में यह स्थिति है और हम एमजेंसी लगाना चाहते हैं। सदन में जैसा कि होम मिनिस्टर ने बयान दिया कि इस सम्बन्ध में कैबिनेट की मीटिंग 26 तारीख को सुबह हुई और उस समय के मंत्रियों को भी एमजेंसी लगाने के बारे में रेडियो से पता चला और एमजेंसी 25 तारीख को रात को लगा दी गई। रात में ही प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपतिजी के पास गई और उनसे एमजेंसी लगाने के आर्डिनेंस पर दस्तखत करा लिये

This is the height of dishonesty. This was a fraud on Constitution.

Nothing less इसका भाग से क्या प्रावधान हो सकता है, इसके बारे में भी मंत्री महोदय विचार करें। कल को फिर कहीं ऐसा न हो कि एक व्यक्ति चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो या जनता पार्टी का हो, इस तरह की हरकत कर बैठे। यह किसी राजनैतिक दल की चाल नहीं है जो 19 महीने तक देश में हुआ है वह दुबारा न हो इसकी हमको तैयारी करनी चाहिये। 19 महीने में जो कुछ घटनाएं घटी हैं उनका लाभ उठा कर हमको क्या करना चाहिये इस पर हमें विचार करना चाहिये।

अगर किसी का दिमाग विगड़ जाए और वह तानाशाह बनने की इच्छा अपने अन्दर पैदा करे, कोशिश करे तो किस प्रकार की उस पर रोक लगनी चाहिये मंत्रीजी इसके बारे में विचार करें। जहां तक जनता पार्टी का तबाल है वह देश में प्रजासत्तक चाहती है, प्रजातंत्रीय ढंग से काम करना चाहती है, जिस

दिन जनता हमें नहीं चाहेगी हम अपने आप अलग हो जायेंगे और जिस पार्टी को जनता चाहेगी वह आकर बैठ जायगी। लेकिन कुछ बैक्स भी होने चाहियें। मान लें एमरजेंसी लग गई। तब क्या वह सालों तक चलती रहेगी? क्या उसकी कोई लिमिट नहीं होगी? मैं चाहता हूं कि एमजेंसी के बारे में अगर आर्डिनेंस होता है तो तीन महीने के अन्दर-अन्दर सदन की एप्रूवल उसको मिलनी चाहिये और वह भी सिम्पल मजोरिटी से नहीं बल्कि तीन चौथाई मजोरिटी से। ऐसा आपने किया तो इसमें किसी भी पार्टी को दूसरी पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेगा, उनकी सहमति के बगैर एमरजेंसी चालू नहीं रह सकेगी। उसके बाद हर चार या छः महीने बाद या तीन महीने के बाद सदन का एप्रूवल लेते रहना चाहिये। इतना ही नहीं कि एक बार एप्रूवल ले लिया और उसके बाद एक-एक साल के बाद लेते रहें। हर छः महीने के बाद कम से कम सदन के सामने वह चीज आनी चाहिये और सरकार को बताना चाहिये कि क्या वह इसको जारी रखना चाहती है और तीन चौथाई बहुमत से यह चीज पास होनी चाहिये और तभी यह जारी रहनी चाहिये।

जब एमरजेंसी लगाई गई थी और हमारे इधर के भाई भी ऐसे चुप बैठे रहे जैसे द्रोपदी का चीर हरण हो रहा हो और दुर्योधन भी सभा में हों, द्रोणाचार्य भी बैठे हों और शांति से बैठे रहें, क्योंकि हमने उनका नामक खाना है इस वास्ते हमको चुप बैठे रहना चाहिये, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। पीछे इनकी हालत यही हो गई थी। मंत्री लोग शायद भय के कारण, अज्ञान के कारण या कुर्सी के सालाक में, या सब मिला कर चुप बैठे रहे और किसी ने खबर नहीं खोजी। अगर दो

[श्री फखर लाल गुप्ता]

भारत ने खबर खोली होती तो शायद वह हालत न होती जो हुई, काँग्रेस पार्टी की भी वह हालत न होती जो हुई देश में तानाशाही न चलती और कलंक का टीका न लगता, भारत के इतिहास में यह घबरा न लगता जो अब लगा है। पार्टियां धाती हैं और जाती हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस तरह की तानाशाही अनपैरेल्लड थी दुनिया के डेमोक्रेटिक देशों के लिए।

16.00 hrs.

मैं यह भी चाहता हूँ कि एमरजेंसी में भी लाइफ का फंडमेंटल राइट खत्म नहीं होना चाहिये। मुझे याद है कि जब मैं ने अपनी रिट वीटीशन विल्ली हार्ड कोर्ट में दायर की तब तो कभी वकील नहीं रहा हूँ, मैंने अपने मित्र से कहा कि वह मेरी बकालत कर दे। वह चढ़े हो गए और जैसे ही वह एडमिट हुई, शाम को मीसा का वारंट उनके घर पर पहुंच गया। उनसे लिखा लिया गया कि मैं उनकी बकालत करूंगा तो उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा। उससे लिखा लिया गया कि मैं उनकी बकालत नहीं करूंगा। तब जा कर वह वारंट रद्द हुआ। कोई वकील मेरी बकालत करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरी याचिका केवल यही थी कि मुझे खाना अच्छा मिलना चाहिये, रहने के लिये जगह अच्छी मिलनी चाहिये। मैंने स्वयं प्रार्थमिक जज के सामने की। मैं ने कहा कि ठीक है जो मीसा का एक्ट है उसके तहत मुझे जेल में रखा जा सकता है, जेल कौन सी होनी चाहिये यह सरकार तय करेगी, यह भी ठीक है लेकिन जेल में अगर मुझे ऐसी कोठरी में रखा जाता है जिसके चार कोनों में काले साँप हैं तो क्या कोर्ट इंटरवीन करेगी या नहीं? एक सवाल मैंने यह रखा कि खाना मुझे मिले इसकी मांग करने का मुझे अधिकार

है या नहीं? मीसा के तहत खाने में केवल नमूने आप एक प्राइंस चावल देते हैं और कुछ नहीं देते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या आप इंटरवीन करेंगे या नहीं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जस्टिस प्रकाश नारायण ने उस समय यह कहा था कि गुप्ता साहब, आपको लाइफ का मौलिक अधिकार भी नहीं है, जीने का मौलिक अधिकार भी नहीं है। इसलिये यह कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। अब आप बताइये कि क्या हालत थी। प्रटीनी जनरल ने कहा था लोगों को जीने का अधिकार भी इमरजेंसी में नहीं है। मुझे याद है वह शाम जब हमारा पहली बार इंटरव्यू हुआ था 7, 8 महीने के बाद और जब मेरा छोटा बेटा पहली बार मिलने के लिये आया। उमने कहा पिताजी हम यहां से जाना चाहते हैं। मैं कमला नगर में रहता था, वहां से कहां जायेंगे? मैं ने सोचा शायद नई दिल्ली में रहना चाहते होंगे। तो कहने लगा नहीं। मैं ने पूछा कहां जाना चाहते हो? कहता है कि जेल से अगर आप छूट गये तो हम तो इस देश से जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रटीनी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी को गोली भी मार दे तो प्रदातल कोई कार्यवाही नहीं करेगी। यह बच्चों के दिमाग में बात थी। इसलिये जो बच्चों के दिमागों को, परिवारों के लोगों को टैंचर किया गया, वह चीज इसमें से निकाल दी जानी चाहिये। इगलैंड के अन्दर लड़ाई हो रही थी, वहां भी इस तरह का प्रावधान नहीं था। लड़ाई होने हुए भी वहां पर कुछ लोगों के अधिकार रहे। इसलिये मैं मांग करूंगा सरकार से और जनता पार्टी सहमत भी होगी, क्योंकि जनता पार्टी अत्याचार के ऊपर, लोगों के ऊपर कुर्सी पर नहीं बैठना चाहती है। जनता पार्टी तभी तक कुर्सी पर रहेगी जब

रक लोगों की इच्छा होगी। इसलिये जो जीवन का मौलिक अधिकार है वह हमरज्सी में खत्म नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय कामत के बिल का समर्थन करता हूँ।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर)  
सभापति महोदय, भारतवर्ष के संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ कर

सभापति महोदय एक भ्रजं बरुगा विजरा संक्षेप में कहिये क्योंकि इस बीच में 6 नाम धा चुके हैं। एक घंटे में सबको बालने की गुजाइश होना कुछ मुश्किल है।

डा० रामजी सिंह, भारतवर्ष के संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ कर भारतीय संविधान की धारा 352 का प्रावधान किया था जिसमें आपातकालीन स्थिति लगाने के विषय में प्रावधान था। लेकिन संविधान बनाने वाला की भावनाओं की हन्या करने का अधिकार उसके बाद कांग्रेसी सरकार को हुआ, और भारतवर्ष में आपातकालीन की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ। हम जानते हैं कि यहाँ भारतवर्ष में कोई इमरजेंसी 1975 में नहीं लगी। हमारे माननीय कबरलाल गुप्त कहते थे कि 1975 में इमरजेंसी लगी, लेकिन हमारा तो कहना है कि भारतवर्ष में इमरजेंसी शायद उठी ही नहीं। 1968 से लेकर 1971 के समय का छोड़ कर 1962 से जा आपातकालीन स्थिति लागू की गई थी वह 1977 में तब समाप्त हुई जब जनता सरकार बनी। इसीलिए एक ऐसी अनिर्वाय और आपातकालीन परिस्थिति को सामान्यरूप में लागू कर देना भारत की राजनीति के साथ एक वैभवावृत्ति है, और इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि सचमुच में अब यह विचार करने की आवश्यकता हो

गई है कि अब 19 महीने की आपातकालीन परिस्थिति चाहिये या 19 वर्षों की, अगर शकए और दुष्काए भारतवर्ष की कहीं चरितार्थ हो गई तो इस बार कबर लालजी और हम लोग 19 महीने के लिये नहीं बल्कि शायद 19 वर्षों तक आपातकालीन परिस्थिति में जूझते रहेंगे। इसीलिये हमारे वयोवृद्ध कामत साहब का जो प्रस्ताव है, वह कोई प्रक्रिया के स्वरूप नहीं, बल्कि उसमें सचमुच में एक निर्देश है। हम जानते हैं कि इस आपातकालीन स्थिति को भी भारतवर्ष की राजनीति के लिये उपयोग किया गया था, अपनी सत्ता को और अपने एकछत्र राज्य को बरकरार रखने के लिये किया गया था। प्रफसोस है कि भारतीय संविधान में उसको दंडित करने के लिये किसी धारा का निर्माण नहीं हुआ है।

आपातकालीन परिस्थिति एक विशेष परिस्थिति में होती है, सामान्य परिस्थिति में उनका उपयोग निश्चित रूप से संविधान की भावना का हनन है। इसीलिये हम जो भी कहते हैं, खास कर जब आपातकालीन परिस्थिति में हम न्यायानय में नहीं जा सकते जब हम निर्वाचन टाल सकते हैं, विशेष परिस्थिति हो जाती है उस में हमें बहुत सोच-समझ कर इसको लगाना चाहिये। इसीलिये हमारे कामत साहब का जो सुझाव है वह कोई ऐसा नहीं है जो किसी को मान्य न हो। यहाँ जो मंत्री महोदय, बैठे हुए हैं, मैं उनके ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि कामत साहब का सुझाव तो बिल्कुल सर्वमान्य सुझाव है, लेकिन पहला सुझाव यह है कि संविधान की सम्बद्ध धारा में इटरनल डिस्टेंस की जगह आर्म्ड इन-सैरकशन रख दिया जाए।

[डा० रामजी सिंह]

भारत एक बड़ा और महान् देश है, यहां छोटे-छोटे और आंतरिक डिस्टर्बेन्सेज तो होते ही रहते हैं। अभी जब इंदिराजी दक्षिण में गईं तो डिस्टर्बेन्सेज हो गए, तो क्या हम इस पर एमजेंसी थोप देंगे? वाराणसी में हमारे मित्रों के द्वारा, उनके सहयोग से साम्प्रदायिक दंगा हो गया, तो क्या हम आपात्कालीन परिस्थिति लागू कर देंगे? नहीं।

इसीलिए हमारा चिन्तन सुस्पष्ट होना चाहिये कि इंटरनल डिस्टर्बेन्सेज तो इतने बड़े देश में होते ही हैं। कौन सा ऐसा देश है, जहां इंटरनल डिस्टर्बेन्सेज नहीं होने हैं? लेकिन हम आपात्कालीन परिस्थिति तभी लगावेंगे जब हमारी अखंडता और सार्वभौमता को किसी तरह से, चाहे वह नागालैंड, काश्मीर या कन्याकुमारी, आन्ध्र या बिहार, कहीं से उमको चुनौती मिलेगी। इसलिये इसको स्पष्ट करना चाहिये।

उनका दूसरा सुझाव है कि यह दो महीने के लिये जो लगाते हैं तो वह दो महीने के लिये नहीं 1 महीने के लिये होनी चाहिये। सचमुच में—

प्रभुता पाई काहूँ मद नाहि ।

सत्ता पर अग्रर अंकुश नहीं होगा तो सत्ता स्वेच्छाचारिणी हो जायेगी। इसलिये दो महीने की अवधि को एक महीना कर देना चाहिये।

अगर सब संसद् का चलता रहे, और एक महीने तक उसकी स्वीकृति न हो तो वह यों ही समाप्त हो जायेगा, उस अवधि को कम करके 14 दिन किया गया है। यह जनता मरकार आपात्कालीन परिस्थिति की भुक्तभोगी है, इसलिये उसको कम-से-कम यह सुझाव स्वीकार करने में उदारता दिखानी चाहिये

और उसके लिये लोगों के यश का भागी होना चाहिये।

हम जानते हैं कि आपात्कालीन परिस्थिति के प्रावधान के द्वारा हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया में तानाशाही पहुँचती है। जर्मनी में हिटलर ने भी एमजेंसी के प्राविजन्स के द्वारा ही कास्टीट्यूशनल डिक्लेट्रिगिप स्थापित की और उसी प्रकार भारत में इन्दिराजी ने किया। मैं कानून का पंडित तो नहीं हूँ, हमारे कानून मंत्री बैठे हैं, वह बतावेंगे कि इन्दिराजी ने एमजेंसी को लागू करके कोई अवैधानिक काम तो नहीं किया है। लेकिन सचमुच में उन्होंने अनैतिक काम किया है, जनतंत्र का हनन किया है। इसलिए यह आवश्यक है कि कहीं कोई नई इन्दिरा गांधी भारतवर्ष की भूमि पर पैदा हो कर जनतंत्र का हनन न करे, इसलिए उस पर संसद् का अंकुश लगना चाहिए। गैडकल ड्यूमीनिस्ट पार्टी के श्री एम० एन० राय ने भी कहा था कि कहीं-कहीं संसदीय प्रजातंत्र की सीढ़ी पर चढ़ कर ही तानाशाही पैदा होती है, और उन्होंने इसके प्रति सावधान किया था। हम देखते हैं कि भारतवर्ष में इस संसदीय प्रजातंत्र के आपात्कालीन परिस्थिति के प्रावधान की निरक्षुता और स्वेच्छाचारिता की सीढ़ी पर चढ़ कर ही तानाशाही आई। इसलिए जब तक हम पर अंकुश नहीं लगेगा—जब तक संसद् के दो-तहाई मत का अंकुश नहीं रहेगा और उपस्थित सदस्यों में से तीन-चौथाई सदस्यों की स्वीकृति नहीं होगी—तब तक सत्ताधारी दल के फिर निरंकुश होने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि सबको सत्ता की भूख और अभिलाषा होती है।

लोग कह सकते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ है। दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों के इतिहास को देखने से पता

बलता है कि इंग्लैंड में वहाँ के राजा को आपातकालीन परिस्थिति को लागू करने का अधिकार था, लेकिन थिप मनी केस और डिफेंस बिल एक्ट, 1914-15 में यह अधिकार सरकार और संसद को दे दिया गया है। अमरीका में भी आपातकालीन परिस्थिति, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है:

“Extraordinary conditions do not create or enlarge constitutional powers.”

अगर कोई सरकार मजबूत है, तो कोई विशेष परिस्थिति आने पर उसका मुकाबला करने में समर्थ होनी चाहिये। लेकिन उम के लिये संविधान की धाराओं को तोड़ना-मरोड़ना और अधिक अधिकार प्राप्त करना गलत है।

आस्ट्रेलिया के संविधान में भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जर्मनी की राइख ड्राग भी 1919 में इमरजेंसी प्रावधान स्वीकार किया गया था। यह देखा गया है कि जहाँ भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए प्रावधान है, वहाँ तानाशाही आई। जर्मनी के संविधान में आपातकालीन परिस्थिति का प्रावधान था, इसीलिए वहाँ दुनिया की सब से निष्कृष्ट, गरीब और कुत्सित तानाशाही आई। फ्रांस की फ्रिफूट रीपब्लिक के 1958 के संविधान में आपातकालीन परिस्थिति लागू करने के सम्बन्ध में शंका है। प्रेजिडेंट उसे लागू कर सकते हैं, लेकिन इस के लिये उन्हें प्रधान मंत्री और संसद के अध्यक्ष की राय लेनी होगी।

अगर सत्ता पर शंका नहीं होगा, तो सत्ता का स्वाभाविक बर्तन होता है कि वह

स्वेच्छाचारी हो जाती है। इसलिए मैं सरकार और सदन को कहना चाहता हूँ कि मन्नीय सदस्य, श्री कायत, ने जो साधु प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, वे उन्हें स्वीकार कर लें, और कानून मंत्री उन के विधेयक को स्वीकार कर के यश के भागी बनें।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE  
(Jadavpur): Mr. Chairman, Sir, we wanted the Bill to be discussed to-day, because the Government is now formulating its views on the proposed amendments to the Constitution. This is an Article, we feel, on which this House should express its views in no uncertain manner. We have seen that this Article in the Constitution was utilized, rather mis-utilized, to bring about a situation in this country which was wholly unreal. Article 352 was taken recourse to by a power-hungry executive authority, by a dictator in this country for the purpose of introducing a fake Emergency, because the rationale behind Article 352 was not present when this proclamation was issued in June 1975. We find that Article 352 has become a method of introducing dictatorship in this country, in a constitutional manner. The fundamental question that we have to keep in mind is that our Constitution provides an Article viz. Article 352 by making misuse of which a dictatorship can be introduced in this country. And for 19 months the people of this country had the most sordid experience. We have seen that every stream of life in this country was polluted. Parliament was made a rubber-stamp. We have seen how the Judiciary was decimated. We have seen how the Executive was made to kow-tow to the desires nepotism, jobbery and corruption of a single individual and her family. We have seen how a half-educated, arrogant and perverted young man was sought to be put up in this country as the Royal Prince, and how the whole

[Shri Somnath Chatterjee]

Administration was dancing to his tune. The revelations which are coming before the Shah Commission should be more than an eye-opener in this context. We have seen how even in the university campuses, Emergency powers were mis-utilized. We have seen that in industry, trade, trade-union movement, everywhere draconian measures were taken under the garb of Emergency powers. We ought to think whether we should have, in our Constitution, a provision which is the method of Constitutionally introducing a dictatorship in this country. We now ought to realize that this nation has learnt a life's lesson. If we don't—if we have the opportunity and if we don't—have that political will to realize that there is a possibility of a recurrence of such a situation in future, not only shall we fail ourselves, but we shall also fail the posterity and the future of this country.

There is no definition anywhere of the word 'internal disturbance'. Any and every situation could have been described as relating to internal disturbance. Even a Cabinet was bypassed. We have seen it. Even the modicum of complying with the rules of business was not there. A person individually decides to declare Emergency. If the President cannot stand up against him, if he cannot even insist on a Cabinet decision—as we have seen today—the country comes under an Emergency. Even then it was a duplicate Emergency. There was an Emergency which was on, from 1971, on account of the actual war on this country. You were there, Sir, when the external war was on. When there was that aggression, this House unanimously approved the proclamation of Emergency. Because we realised that it was a genuine threat to the independence of this country, not a single Member failed in his duty, but we saw to our dismay how that emergency continued indefinitely, although the war lasted only 13 days. We had been asking, in this House, for the

withdrawal of the proclamation of the emergency of 1971, but there was no response. It was sought to be justified on the ground of economic considerations.

Then came the internal emergency, a duplicate emergency, a hoax that was perpetrated on the people. It was realised that it was not for the benefit of the people of this country that this second proclamation was issued. It was for the benefit of a single individual and her progeny. It was to keep up the morale of a party which was reeling under corruption. It was to try to save and protect an administration and a Government which was of corruption by corruption for corruption. This was the object of the second emergency.

And in the process, when blood was tasted, more and more power was sought to be taken. We are seeing every day in the papers how MISA, COFEPOSA and DIR were misused, how the nation was paralysed, how even the ethos of this nation was paralysed. The trade union movement was completely stopped, the student movement was stopped. As I said, Parliament because a handmaid for the purpose of introducing and carrying out ruthless legislation. We found how, under the garb of emergency provisions, the other Constitution Amendment Bill came, how the Prime Minister's election was sought to be kept above the law. The people of this country have no right to work, no right to a subsistence living, but at least they had the right of liberty, but that right too was taken away.

We have seen what a perverted outlook they developed because of the emergency provisions. The Attorney-General of this country, who is paid out of the exchequer, which is contributed by the people of this country, was solemnly arguing on behalf of the then Government that there was no right of liberty, no right to life in this country, and that was upheld. So

should we have anything in this Constitution which can help bring about such a situation again in this country? Therefore, my appeal to the hon. Minister and to the Government is to see that this blot on the Constitution is removed and removed as early as possible.

In so far as Mr. Kamath's Bill is concerned we are not supporting it in its present form, because we do not know how insurrection will be defined, how it will be construed. We can certainly understand actual war in which some of the people have to make a sacrifice even of their fundamental rights, but what is armed insurrection or armed rebellion or armed revolution, whatever it is? Nobody would know what it means. Supposing there is a disturbance like the PAC trouble in U.P. during the tenure of the last Government, would that justify the declaration of an emergency under article 352? Or, if there is what is known as the Naxalite movement, would that justify the declaration of an emergency? These are the questions which are still agitating the minds of the people.

I believe the Government is considering them, and they ought to think in the greatest depth as to whether these Powers should be made available to any Government, present or future. You do not know what sort of Government may come in future. There are machinations going on. All sorts of attempts will be made. Industry, big business, monopoly houses etc. are not happy with the change of Government. There are people with vested interests. Unfortunately the performance of this Government in economic field has not been such as to enthuse the people. We do not know what will happen if you allow such a draconian power to remain available to the people who have got the least sense of proportion or the least sense of concern for the people and who could take recourse to it for their per-

sonal interest. This state of affairs has to be altered. That is our submission. We had seen during the last regime how all other different provisions of law had been ignored, how official position had been misused for the sake of the Prime Minister and her progeny, how her cohorts were shielded, how innocent people were harassed. Everything was for the sake of emergency. People were hoodwinked. We have seen how consciously an attempt was made to put a halo round an individual. We have seen how an individual was projected to be an infallible in this country and how she was equated with the country as a whole. We have seen that. At the same time, we had watched in the last House how the then Members of the Ruling party were vying with each other to drumbeat the so-called achievements of that dictator and how they were competing with each other in exhibiting spineless sycophancy and thumping their desks to extol the depredations which had been shamelessly committed on the Constitution of India and the democratic way of life in this country. A Parliament which was brought under thumb was approving all sorts of infamous legislations. We were protesting in vain. The Parliament was treated to be a plant instrument for the purpose of carrying out all sorts of illegal provisions and passing all sorts of dictatorial laws. Therefore, we were saying that people's representatives will decide on merits but unfortunately, we had not been able to stand up to that position during the last emergency. We have seen how in the so-called constitutional manner a rape was committed on the Constitution. Therefore, the sooner we completely obliterate it from the Constitution, the better for the country.

People have learnt the lesson, of their life. We have to generate public opinion. But if we leave such power in the hands of executive which has no hesitation to use it for party purposes or for personal purposes the future of this country will again be un-

[Shri Somnath Chatterjee]

certain and there may be dark days again. Therefore, our submission is that Article 352 has so far been utilised in this country not with the object with which it was introduced in the Constitution by the authors of the Constitution. There was a belief and it was stated on the floor of the Constituent Assembly that when the country's security will be really and genuinely at stake, then and then only this will be taken recourse to.

The mass media was completely brought under thumb. It was sought to be given to the people that there were such disturbances that the country's administration could not be run; its integrity was being threatened and its security was going to be threatened. That was the propaganda that was going on. On that falsehood, a structure was built up. The whole object was not of the good of the country and of the benefit of the people. Therefore, on behalf of my Party, we do request the Government immediately to bring about necessary changes in the Constitution of India and so far as Article 352 is concerned, we do not believe in giving power and trying to put restrictions on it. It is because those restrictions become meaningless restrictions. Do away with the source of power which has been corrupted, which has been misused and which has been utilised not only for the sake of building an empire but also a financial empire.

Since we are not concluding the consideration of this Bill today, I would request the hon. Minister to kindly consider it. Let the people of this country be saved from the misuse of the Constitution. Unless you do away with the provision of Emergency from the Constitution itself there may be many Indira Gandhis who may be waiting to do the same. Don't ignore that.

**SHRI CHITTA BASU (Barasat):**  
Mr. Chairman, Sir, I have got my mixed reaction to this Bill moved by my hon. friend, Shri H. V. Kamath.

I have got my mixed reaction because of the fact that although I agree with him and I, naturally, share his anxiety to provide for certain safeguards against the misuse of article 352 of the Constitution of our country, yet I have got also a feeling that this very article is not necessary to be there in the Constitution of our country particularly in view of the fact that it has been misused or mis-utilised to the extent possible.

\*Shri Kamath is not present in the House. I would have liked to take this opportunity to remind him of his staunch opposition that he voiced in the Constituent Assembly when the Constituent Assembly was debating on this particular article. I only want to reproduce from his speech what he said at that time. I must say it is not Mr. Kamath's view which has been reflected in this Bill. I do not say it in a spirit of disrespect or disregard for him. I quote:

"The closest approximation, to my mind, is reached in the Weimar Constitution of the Third Reich which was destroyed by Hitler taking advantage of the very same provisions contained in that Constitution. That Weimar Constitution of the Third Republic exists no longer and has been replaced by the Bonn Constitution. But those emergency provisions pale into insignificance when compared with the emergency provisions in this chapter of our Constitution."

This shows that he was very clear in his mind, even at the stage of drafting of the Constitution and at the time of the inclusion of the emergency provisions under article 352 which was then article 275 of the draft Constitution of our country, that even the emergency provisions included in the Weimar Constitution paled into insignificance as compared to our emergency provisions. Naturally the House will understand the feeling of Mr. Kamath as a member of the Constituent Assembly then.

Again, he says:

"I, therefore, earnestly appeal that this Chapter should not be passed in a hurry. It should be amended in such a way that not merely the liberty of the individual but also the freedom and powers of the constituent units are not unduly suppressed. We should alter and revise the Chapter so as to see that the liberties guaranteed in this Constitution are real."

Mr. Kamath comes to the House to replace internal disturbances by armed insurrection. He was very clear at that time in his mind what was meant by armed revolt. He said on 2nd August, 1949 in the Constituent Assembly as follows:

"Let us remember that Constitution can be subverted not merely by agitators, rebels and revolutionaries, but also by people in office, by people in power."

Therefore, he himself admitted at that time that the Constitution cannot only be subverted by so-called armed insurrection, or armed revolt or armed rebellion, as you may say, but it can very well be subverted by those who are holding power even in a non-violent way.

Therefore, I am not in complete agreement with the provision he wants to make in order to provide more safeguards against the misuse of this Article. As a matter of fact I like to make it very clear that in any democratic country there is no provision of emergency of this nature as has been very ably pointed out by friends sitting on the opposite side. I do not like to dilate on that point. In many countries, there is no such provision of emergency to be in the Constitution itself. But, having regard to the fact that our country was a victim of aggressions from neighbouring countries, there may be a necessity of having some provision of this kind of emergency only in order to meet the threat of external aggression. Therefore, what I want to make it clear is this. Even if the Article

352 is to be retained, it can be utilized only on the occasion and sole occasion of external aggression. On no other consideration, whether it is internal disturbances or whether it is armed insurrection or armed rebel, there should not be such a constitutional provision in our country.

Mr. Kamath has not taken pains to explain what he really meant by armed insurrection. I do not know how you have defined the words 'armed' and again 'rebellion'. I am in complete agreement with Mr. Somnath Chatterjee when he says that these very words either "internal disturbances" or "armed insurrection" or "armed rebellion" can be very well utilized in the very same way as Mrs. Gandhi used to destroy democracy and imposed dictatorship in our country. Therefore, I am very clear in my mind about it. If there is, at all, a necessity of having an emergency provision that must be confined only to a situation when the country is faced with external aggression. On no other situation, there should be any use of that particular provision for emergency.

I am also in agreement with providing certain safeguards. I am happy to see that Government itself is working on providing certain safeguards against misuse. In that connection Government should also consider the proposals which are emerging from this House on the occasion of this debate.

There is a provision in the Constitutions:

"Notwithstanding anything in this Constitution,— (a) the satisfaction of the President mentioned in clause (1) and clause (3) shall be final and conclusive and shall not be questioned in any court on that ground;

(b) subject to the provisions of clause (2), neither the Supreme Court nor any other court shall have jurisdiction to entertain any

[Shri Chitta Basu]

question, on any ground, regarding the validity of—

(i) a declaration made by Proclamation by the President to the effect stated in clause (1); or

(ii) the continued operation of such Proclamation."

This should be deleted. The satisfaction of the President as to whether there has arisen a situation or condition for the promulgation of the Emergency cannot be questioned in any court of law. This still finds a place in the Constitution of our country. I would urge on the Government that, in formulating their position in the matter of reframing of article 352, they should apply their mind and see that this kind of provision which prohibits questioning the validity of the satisfaction of the President is omitted. The courts should have jurisdiction to see whether the situation did really arise as warranted, for the promulgation of the Emergency.

I am happy to see that the Government proposal contemplates this:

"A provision may also be introduced that the proclamation of emergency would cease to be operative whenever a resolution to that effect is adopted by the Lok Sabha by a simple majority of the Members of the House present and voting. It may also be provided that Members of the Lok Sabha not less than one-tenth of its total membership could requisition a meeting of the Lok Sabha for the purpose of considering the continuance of a proclamation of emergency."

This is a welcome safeguard in the matter of curbing the possibility of misuse.

Before concluding, what I would urge upon the Government is that there should not be any Emergency provision in our Constitution, and if at all the need is felt then that should be restricted only to the situation aris-

ing out of external aggression—the emergency provision should not be used for any other situation. Also in the matter of the right of the President to promulgate such an Emergency, other safeguards should also be provided for. Some of them have been suggested by our friend, Mr. Kamath; some have been suggested by some other Members also; and some of them may also emerge from our future dialogue.

With these words, I conclude; and I would request that Government should apply its mind and formulate a comprehensive provision in this regard.

MR. CHAIRMAN: The hon. Members will remember that the time for the discussion of this Bill moved by Mr. Kamath was extended by one hour, which will be over at 4.48 p.m. Is it the pleasure of the House that the time be further extended by another hour—for the discussion of this Bill?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: So, the time has been extended by another hour. Chowdhry Balbir Singh.

श्रीचरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) :  
सच्चापति महोदय, श्री कामत साहब ने बिल पेश किया है कि इस देश में फिर से इमर्जेंसी लागू न हो सके, लेकिन कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही हैं कि इस देश में सनस्र हमला अगर हो जाये तो एमर्जेंसी लागू की जा सकती है। पहली एमर्जेंसी लगी तो एक साबर ने कहा —

नेता बन्धे की लाठी है, ठीक पड़ी तो ठीक, गही तो कौनों की शोली में कुछ घास कुछ बीज।

देश की सरकार अगर ठीक ढंग से चल रही हो तो देश में सनस्र हमला कैसे हो पायेगा ?  
घाजाबी के बाद 3 सप्ताहों हुई हैं—  
1962, 1965 और 1971 में। अगर

तीनों बार एमजेंसी लागू की गई है तो उस समय अपोजिशन का एक भी मेम्बर पार्लियामेंट या किसी प्रसेम्बली का मेम्बर पकड़ा नहीं गया, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इसमें सारे देश के अपोजिशन के नेताओं को, जिन्होंने 1962, 1965 और 1971 में सरकार के साथ कब्जे से कब्जा मिला कर लड़ाई में हिस्सा लिया था, इसी सदन में जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम से जो छीना गया है, हम पूरी कोशिश से उसको वापिस लेंगे, उन सब को जेलो में बन्द कर दिया। उन लोगों ने जो भी सरकार उस वक्त थी उसका साथ दिया था।

1965 में आपको याद होगा, जब हमला हुआ तो यहाँ पर आर० एस० एस० के वालिन्टियर्स ने चौकोर पर पहरा दिया, पुलिस का काम भी शुरू किया। मैं कोई आर० एस० एस० का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन यह बात कहने के लिए तैयार हूँ, जब देश को कोई खतरा था तो इस देश का हर आदमी उस खतरे के खिलाफ, जो भी सरकार उस समय थी, उसके साथ था।

अब जो यह बात है कि अगल सशस्त्र हमला हो जायेगा तो एमजेंसी लग जायेगी, तो कोई भी अधान मंत्री अगल चाहेगा कि एमजेंसी लागू करनी है, जैसे कि इन्दिरा जी ने लागू की थी, तो किसी भी जगह सशस्त्र हमला कराया जा सकता है। 200, 400 आदमी लगा कर बन्दूक से हमला सा करा दिया। हिटलर ने क्या किया था? उसने पार्लियामेंट में आग लगावा दी थी और कितने उसके मुखालिफ थे, उन सब को पकड़ कर जेल में बन्द करवा कर गोली से मारकर खत्म कर दिया था।

तो यह एक नया रास्ता न निकाला जाये कि सशस्त्र हमला देश में हो जाये तो एमजेंसी लग जाये। अगल देश की सरकार

ठीक ढंग से काम करेगी तो किसी की जुरत नहीं होगी, देश के लोग उसे बर्दाश्त करेंगे। इसमें अभी कभी रह गई हैं। कानत साहब से कोशिश तो की है इन कमियों को ठीक करने की, लेकिन इसमें भी हमें सोचना चाहिए कि कभी देश में अगल ...

SHRI P. K. DEO: May I point out Sir, that there is no quorum in the House?

MR. CHAIRMAN: The bell is being rung....

There is no quorum yet. Let the bell be rung again. Now, there is quorum. The hon. Member may continue.

श्रीधर बलबीर सिंह: सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि इस में भी जो यह वर्ज किया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर इंटरनल सशस्त्र हमला अगल हो जाये तो एमजेंसी लागू की जाये, मैं तो इस के भी खिलाफ हूँ। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि 1962 में, 1965 में और 1971 में इस देश पर हमला हुआ तो आप को पता है कि सारा देश एक आवाज से सरकार के पीछे था और इस हद तक पीछे था इस सरकार के कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का भी खिताब दे दिया था। वह दुर्गा थी या ताड़का थी यह तो आने वाले तबारीखदा बताएंगे। मैं तो अपनी बात इसलिए कहता हूँ कि उस समय इस सदन के अपोजिशन के जो बहुत बड़े बड़े नेता थे उन्होंने भी उस वक्त सरकार के पीछे अपना सारा समर्थन दिया और उस इंदिरा को दुर्गा का रूप दे दिया। उस ने दुर्गा का रूप धारण किया या ताड़का का यह अब अटल बिहारी साहब बता सकते हैं .....

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): सभापति महोदय, मैं बता दूँ।

**[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]**

यह सत्य नहीं है कि बंगला देश की लड़ाई के समय मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। मेरा भाषण इस सदन में हुआ था। वह कार्यवाही का हिस्सा है। मैंने दुर्गा नहीं कहा। मैं जानता हूँ दुर्गा का क्या महत्व है।

**बीबरी बलबीर सिंह :** इस सदन में नहीं, बाहर आप ने लेक्चर दिया था।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** न मैंने बाहर कहा, न भीतर कहा। न ऊपर कहा, न नीचे कहा, न दायें कहा न बायें कहा।

**श्री सौगत राय (बैरकपुर) :** इंदिरा जी श्रीर दुर्गा का आप के माथ कुछ साल्लुक है, कहां बोले थे यह बात भलग है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभापति महोदय, आप सदन में उस समय मौजूद थे। यह स्पष्टीकरण मैं दे चुका हूँ। बात यह हुई कि उस दिन सदन में कोई हमारे आग्रह के सम्बन्ध में जिन्होंने उन को महिपामुर मदिनी कहा था श्रीर कुछ भ्रष्टाचारों में वह मेरे नाम से छप गया। मैंने दुर्गा नहीं कहा। वैसे उन दिनों मैं इंदिरा जी की इज्जत करता था श्रीर मैंने उन की प्रशंसा की। इस को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उन्होंने जब अच्छा काम किया तो मैंने उन की तारीफ की लेकिन जब गलत काम किया तो उन को उबाड़ कर फेंक दिया।

**बीबरी बलबीर सिंह :** मैं यह कह रहा था कि इस देश के हर आदमी ने जब देश पर कोई खतरा आया है तो सरकार का साथ दिया है चाहे पंडित नेहरू उस समय गद्दी पर रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों चाहे इंदिरा गांधी रही हों श्रीर बाहर के देशों को देखें तो इंग्लैंड में जब सेंकेड वर्ल्डवार हुई तो अपोजीशन की सरकार में शामिल किया गया

था लीडर आफ दि अपोजीशन सरकार में उतने ही जिम्मेदार घोड़े पर थे। तो यह बात है कि मुक्त पर हमला हो जाये तो देश के लोग एक आवाज से सरकार के साथ बड़े हो जाते हैं। 1971 में जो हमला हुआ उस समय पंजाब में अपोजीशन की सरकार थी, भकाली दल श्रीर फ्रंट की कोलीशन सरकार थी। बाकी सारी पार्टियों ने मिल कर सरकार बनायी थी। उस वक्त पंजाब ही सबसे ज्यादा उस हमले का शिकार हुआ था। लेकिन मैं यह फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लोग एक जवान से इकट्ठे हो कर उस लड़ाई में शामिल हुए थे। हम लोग शामिल हुए। हमारा अपना लड़का हवाई फौज में फ्रंट पर काम कर रहा था।

10.59 hrs.

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO in the Chair].

लेकिन इंदिरा गांधी का बेटा उस समय अपनी तिजोरियां भरने में लगा हुआ था। जब पंजाब के श्रीर सारे देश के जवान फौज में अपनी जान हथेली पर रख कर लड़ रहे थे उस वक्त जितने कांग्रेस के मिनिस्टर थे श्रीर इंदिरा गांधी का अपना बेटा ये सारे के सारे पीसे इकट्ठे करने में लगे हुए थे। इंदिरा गांधी का बेटा अपने मायति कारखाने के लिए लोगों से पीसे इकट्ठे कर रहा था या मायति के हिस्से बेचने के लिए लोगों पर दबाव डाल रहा था। ये सारे काम उस समय ही रहे थे श्रीर हमारे बेटे उस समय फ्रंट पर लड़ श्रीर, मर रहे थे। हमारे बेटे वहाँ मरे। मरने वालों के जो बालिवैन थे उन्होंने कोई ब्राह्मों में ब्रांस भर कर नहीं कहा था।

17.0 hrs.

उन्होंने कहा था कि हमें फख्र है कि हम अपने देश के लिए लड़ते हैं श्रीर अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देते हैं। इसलिए

यह इमर्जेंसी जो है वह एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी है। कांस्टीट्यूट प्रसेम्बली में जब इस पर बहुत हुई थी तो यह कहा गया था कि कभी इसका गलत तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। लेकिन गलत तौर पर यह इस्तेमाल की गई है। इसलिए इमर्जेंसी की जो बीमारी है वह कभी भी इस देश में नहीं आनी चाहिए। किसी भी समय किसी आदमी का इस गद्दी पर बैठकर विभाग खराब हो सकता है। जब यहां पर अपोजीशन मजबूत नहीं थी और कांग्रेस की अपनी अन्दरूनी गड़बड़ थी तो हिन्दुस्तान को पाकिस्तान की तरफ से और किसी तरफ से खतरा हो जाता था और यह खतरा तो कभी भी मिट नहीं सकता है। जिनके हाथ में गजमत्ता हो वे अगर कांस्टीट्यूशनल तरीके से किसी डूमरे को राजसत्ता देने के लिए तैयार नहीं या उनके विभाग में फिन्नर आ जाये तो जैसा कि एक शायर ने कहा है :

भ्राता है नाखुदाओं की नीयत में जब फिन्नर उठता है साहिलों से तूफा कभी कभी ।

जब भी कभी देश के नेता का विभाग खराब हो जाये तो वह अपनी गद्दी को बचाने के लिए और इस देश को भाड़ में झोंकने के लिए इमर्जेंसी का सहारा ले सकता है। इसलिए हमें इस प्रकार का कोई भी सहारा नहीं देना चाहिए और किसी भी मेम्बर को इसकी यहां पर हिमायत नहीं करनी चाहिए जिसको कि किसी भी समय कोई नेता विभाग खराब होने पर इस्तेमाल करले और इस तरह से इस देश के करोड़ों लोगों की जिन्दगी और आजादी खतरे में पड़ जाये ।

जब पहले सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में सालिस्टर जनरल बहस कर रहे थे और उस समय हमारे प्रति भूषण जी मुकदमा लड़ रहे थे तो जब ने पूछा था कि अगर कोई निमिस्टर पर्सनल बुझनी की वजह से किसी को गोली मार दे तो क्या मरने वाले के घर वालों को बीटें में जाने का हक होगा तो

सालिस्टर जनरल ने बड़े ही शर्मनाक ढंग से कहा था कि जितनी बेर तक इमर्जेंसी लागू है, किसी भी आदमी को जिदगी का हक भी महुफूज नहीं है। इसलिए संविधान में कोई भी ऐसा अधिकार नहीं देना चाहिए जिसके जरिए से एक आदमी का आदालत में जाने का अधिकार छिन जाये। चाहे एक्सटर्नल हमला हो या इंटर्नल कभी भी इस ढंग की इमर्जेंसी नहीं आनी चाहिए कि हमारा जो न्यायालय में जाने का अधिकार है वह चला जाये। न्यायालय किसी बात पर अपनी राय न दे सकें—एसा मौका कभी भी नहीं आना चाहिए ।

मैं आपके जरिए इस सदन से बधाईस्त करूंगा कि कामत साहब ने जो बिल यहां पर पेश किया है उसमें से "इंटर्नल एमरेंशन और "आयर्ड इनसरेक्शन के जो लपज हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। अगर कभी एक्टर्नल इमर्जेंसी का खतरा होता है तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एग्जक्यूटिव आर्डर्न पर अपनी राय देने का अधिकार कभी छीना नहीं जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सदन में अपनी करूंगा कि इस देश में कभी भी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि न दलील, न अपील, न बकील, यह बात कभी नहीं होनी चाहिए। आपने जो मुझे श्री कामत साहब के बिल पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ ।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Can-  
nanore): I am thankful to Shri H. V.  
Kamath for introducing this Bill. Be-  
cause it provides an opportunity for  
the hon. Members of this House to  
express their views on the question  
of emergency. Mr. Kamath's Bill  
seeks to include in the Constitution  
certain new provisions by which the  
declaration of emergency can be bro-  
ught under certain specific conditions  
and safeguards provided therefor. By  
his Bill he wanted to ensure that  
the House has more frequent opport-

[Shri C. K. Chaudrappan]

unity to discuss about emergency and then to decide whether to extend it or to withdraw it. Another amendment suggested by him is in relation to that portion relating to internal disturbance. He wants to substitute the words 'Internal disturbance' for the words 'Armed Insurrection', for the word 'disturbance' he wants to substitute the word 'insurrection'. Would it serve the purpose? we have gone through the nightmarish experience of emergency in this country? we have seen, however good might be the intentions with which emergency was declared, it might be misused by the executive and by the political leadership in the country for carrying on their nefarious political ends. After having seen all these things, I think, what will satisfy this country would be that in the Constitution there should be a provision that this emergency would be in the context of the country being threatened by a war or a part of the country being threatened by a war or external aggression.

But, in no context, should it be permitted in future; we should not allow emergency to be declared in the country even if it is in the name of armed insurrection. During the elections we heard the spokesmen of the Janata Party denouncing the emergency and proclaiming to the nation that once they come to power they will see to it that in future no power on earth would be able to declare an emergency in India. They promised Constitutional amendment to that effect—I don't know whether it is practicable or not, that is another matter. They declared that they will bring such an amendment whereby no ruler in this country in future could declare an emergency. But what we have seen now is that the Janata party is climbing down from that position and they are now coming to say that emergency could be imposed in case of internal armed rebellion in the country.

Now, it is open for discussion. Whoever sits on that side of the Treasury

Benches, the rules, of this country will interpret any movement as just an armed insurrection and if that movement is against their power and authority, they will fall heavily on it and kill it. I do not think that in our country we have such bad experience of the Executive's misusing the powers of emergency for curtailing the democratic rights thereby destroying democracy. This is not happening only now. In emergency it happened. If you remember the events of this country in the days of 1948—51, you can see how the Communists were butchered like anything—not in dozens but in thousands—and the Communist Party itself was banned as also so many mass organisations in this country where not much of a democracy was there from those who were speaking day in and day out about democracy.

But, to-day, under the Janata Rule, you can see that in Bihar, in the name of Kaldut operation, 29,000 prisoners are behind the bar without facing trial undertrial prisoners. This is a fact. Even those people who were fighting against unemployment, 500 of them, were put behind the bars and they are still behind the bars.

So, what I am saying is that even without emergency when the bourgeois is in power, if they find that there is an element of threat against them from any quarter, whether there is emergency or not they will come down on it very heavily and they will put it down. So, there is no need for emergency for that matter.

It is in this background that I am looking into the provisions of the constitutional amendment proposed here. In our opinion, there should not be any provision in the Constitution under which the emergency can be declared on the pretext of armed rebellion or armed insurrection.

We support emergency only if it is declared in the context of an external threat or in the context of an aggress-

sion by a foreign power on our country. Look at the conditions of the last Lok Sabha when Mrs. Gandhi was in power. She could have got the two-thirds majority in the House if it was required. If the discussion was open in the House every month instead of two months, she could have done it. That was because she had the required majority.

**SHRI P. K. DEO:** You might have supported it.

**SHRI C. K. CHANDRAPPA:** Without your vote she had the requisite majority. In this Bill, Shri Kamath is trying to introduce such provisions by which the Government could be restrained from the misuse of emergency on the pretext of an internal disturbance or armed rebellion. In our opinion, such restraints on emergency would not bear much fruit. Therefore, I am concluding by saying that we support the emergency only under conditions of war and under conditions that there is an external threat, and we do not support any emergency—whatever safeguards are provided—in a situation which will be explained in the name of internal disturbance, armed rebellion or armed insurrection. This is our position.

**SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN (Deogarh):** Mr. Chairman, Sir, anybody who is in-charge of something requires some power to protect that. If no power is given to the person who is in-charge of any property he will not be there for the purpose. Any government which is in power should have some authority according to which—as and when it is required—it will utilise that authority to save the nation either from foreign aggression or from internal insurrection. That is the general policy of any society. It is for this reason that there is provision of Article 352 in our Constitution. Article 352 is very clear about Emergency and other actions. So many persons belonging to different parties, caste and

creed for two years and six months and decided certain policies about emergency. I think, it does not require any amendment as those provisions and principles are very clear.

We are now afraid of the experience which we had during the last twenty months of emergency during Congress rule under the leadership of Smt. Indira Gandhi. Now, the point is whether this Article 352, as it is to be kept, or it be amended as Mr. Kamath desires. I would like to say that if persons of Indira Gandhi's mind, attitude and calibre come to power with such followers as the existing Congressmen, the same thing will happen. The amendment suggested is that instead of two months it will be one month; instead of thirty days it will be fourteen days. Further, instead of bringing the matter to Parliament every six months, it will be brought frequent. Even if these amendments are accepted and people of Indira Gandhi's desire, aspirations and attitude come to power, they will do it. My point is that Indira Gandhi did not do it alone with the authority of Article 352. She did it because she had the brute majority in the Lok Sabha. As and when she desired she brought the changes and amendments in this Constitution. She also brought the changes in the Penal Code, election laws and also in the Constitution. So, even if we carry out the amendments suggested by Shri Kamath such persons as Mrs. Indira Gandhi and the Congressmen will do it. So, I do not find any reason as to why we should be so much critical about the original Article 352. Well, to give clarity to the Constitution you may say it is 14 days instead of one month, I have no objection. But you must be very very clear and cautious

[Shri Pabitra Mohan Pradhan]

about brute majority of a single ruling party. As country must not be ruled by a party in power with more than 2/3 majority. If the country is legislated by a Parliament with 2/3 majority and if those legislatures are subservient to the leader like Shrimati Indira Gandhi, than undoubtedly emergency will be imposed off and on. So, while appreciating the mind, the desire and good intention of Mr. Kamath, I do not find that there will be any good result even if we make any amendments or changes in article 352 of the Constitution. But there is one thing in regard to internal resurrection. Why should we be afraid of internal resurrection? At least I am afraid of internal rebellion. Even after 30 years' of independence our people think that democracy is nothing but dictatorship for any person or party. Whoever likes to do anything, desires to act any way, is prone to do such things, whoever wishes to write anything, writes the same, whoever likes to say anything, does it whether it is legal or illegal, whether it is decent or indecent; whether it is a discipline or indiscipline. In the first instance, this is prevalent among the politicians, intellectuals and educated persons and then other people follow them. Therefore, after independence, democracy has become mobocracy, individual and mass dictatorship. These educated, intellectuals, party bosses and party rank and file are as the roof of this mobocracy and mass-indiscipline. They behave in such irresponsible, illegal, irregular and unconstitutional way so that persons in power willy nilly, resort to such strong action like the one, that is, Emergency which was imposed by the previous Government. So, our Law Minister must think in terms of not making amendments in the constitution, but taking some such steps so that no authority will find opportunity to become dictator as Mrs. Indira Gandhi became. With these words, Mr. Chairman, I conclude.

**SHRI SAUGATA ROY (Barrackpur):**  
Sir, I am happy for getting an oppor-

tunity of discussing an amendment to the Constitution because this is just a rehearsal of the Constitution Amendment Bill. The Constitution Amendment Bill will be brought forward by the Government in this session.

Sir, the Government has already circulated to our party the draft proposals to the Constitution which we are discussing in our party. But I think it may not be proper for me to refer at this stage on the Floor of the House the details of the Amendments proposed to the Constitution by the Government. But it may be said that the amendments proposed by Mr. Kamath are very similar to the amendments that are being proposed by the Government with some additions and alterations. Sir, there we come to the crux of the problem, that is, the approach of the Janata Party on the Constitution Amendment Bill. The hon. Law Minister is telling here and I also heard many of the Janata Party leaders eloquent speech about never allowing the atmosphere of fear that was pervading this country. I have heard them wax eloquently about the things that happened during Emergency and when it comes actually to amending the Constitution, they want to keep the same tradition of imposing internal emergency with minor changes here and there. So, it seems to me that at least the Janata Party and its Governments are coming down to brass tacks, coming down to the reality that such a provision is possibly necessary in order to preserve the integrity of the country. Mine is not a speech in justification of the Emergency.

**SHRI UGRASEN (Deoria):** Wrong interpretation.

**SHRI SAUGATA ROY:** I have got your government's amendment proposals. You are keeping those powers in your hands; do not forget that you have not become rebellious overnight. Any government may need

such powers but the safeguards against abuse rests with the government, with the political parties and the people of the country. Mere constitutional safeguards cannot prevent an such excess as happened during the last internal emergency, they cannot be prevented merely by having constitutional safeguards. Even if Mr Kamath's Bill is enacted into law, what prevents the janta party government declaring any mass movement as armed rebellion and coming upon that in the same way. It is on the goodwill of the government, goodwill of the opposition, the strength of the people in the country that one has to depend to prevent recurrence of such things, not on constitutional provisions alone.

At this stage I want to say that the amendments that Mr Kamath had moved are minimal and marginal they make no change in the original constitution. Instead of internal disturbance we have 'armed rebellion'. What you called internal disturbance before you call armed rebellion henceforth. Instead of two months, you have one month. If you have a majority you call anything armed rebellion and after one month you pass it and you get it renewed after six months. In this country the recurrence of the things that happened during the emergency cannot take place in the face of a conscious alter public opinion, through responsible opposition which will not indulge in such situations as had happened in our country in 1974, an opposition which will not give a call for lawlessness, an opposition which will not call upon the police and the military to disobey orders. I want to say that it is possible for our party, Congress Party, today to create internal disturbances in the country but we do not think that it is what we should do because this new government has come to power and it must be allowed to run its full term and fulfil its pledges to the people so that people see what happens. A democratic society can only be preserved through conscious, enlightened public opinion, through conscious en-

lightened organisations and not through anarchistic mass movements and irresponsible mass movements, not through lawlessness and violence. The democratic society's strength is democratic society itself, democratic polity, democratic people themselves. This is the point I want to put across. Janata Party has talked large and long and waxed eloquent about freedom being restored to the people. What do we see in MP? The Janata Party government headed by an erstwhile Jan Sangh Chief Minister has got a mini-MISA, in the same way they have got powers to detain people without trial. In Sheikh Abdulla's Kashmir another law (An Hon Member MAXIMISA). Government has still got so much powers under COFEPOSA. Draconian powers remain. Let the government have powers, let the government have constitutional provisions and safeguards. We will not allow this government to go autocratic or tyrannical. We as an opposition have that capacity to resist any effort of the Janata Party to become tyrannical. That is the best safeguard for democracy today. As a large party we will function as a responsible opposition. We will not object when it comes to actual constitutional amendment. I can tell the Law Minister before hand that we will not object to his proposal for amendments of the Constitution in regard to internal emergency. We have no objection if you keep those powers. But I only remind you let no situation like that develop again. Let not the government go off the track.

Let not the Government's head be bloated with pride, let not the Government with its majority try to throttle the opposition, let not the Government swerve from democratic behaviour, let not this Government think that it is here to rule for ever and let it remember the events of the last six months in this country and remember that the people of this country can, and if given power, possibly change any system, however tyrannical, how

[Shri Saugata Roy]

ever autocratic however powerful it may be and whatever majority it may have. As long as the people of the country are there, I think, a few constitutional safeguards alone are not necessary. The present Government should keep this democracy alive and vibrant.

श्री राम सेबक हजारी (रोसड़ा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री कामत, ने संविधान के आर्टिकल 352 का संशोधन करने के लिए जो विधेयक रखा है, मैं उस के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ ।

संविधान के निर्माताओं ने जिस भावना और उद्देश्य से संविधान की रचना की थी, उसे देखते हुए उन्हें यह विश्वास न था कि इस देश में हिटलर जैसा कोई आदमी पैदा होगा, जो संविधान की ध्वजियाँ उड़ायेगा । मैं आप के माध्यम से विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुकर्म किये और संविधान की जो भवहेलना की, भारत की जनता ने उन्हें उस भी सजा दे दी है । मैं सरकारी पक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि संविधान की भावना और उद्देश्य की देखते हुए उस में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है । अच्छे विचारों के लोग, जिन्हें देश और लोकतंत्र के प्रति प्रेम होगा कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, जो पिछले सरकार और कांग्रेस के लोगों ने किया है इस लिए देश के लिए जो बहुत पवित्र चीज है, जिस की शपथ हम लेते हैं, उस में कोई परिवर्तन हमें नहीं करना चाहिए ।

एक कहावत है कि एक आदमी ने बैब जो से पूछा कि आप ने मुझे बैंगन खाने से मना किया है, तो आप स्वयं क्यों खा रहे हैं । बैब जी ने कहा कि यह तुम्हारे लिए बर्जित है, मेरे लिए बर्जित नहीं है । यह कहावत श्रीमती इन्दिरा गांधी पर बरिदाय

होती है । उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया और देश की स्थिति को बिगाड़ा और कहा कि हम यह काम देश की प्रगति और विकास के लिए कर रहे हैं, जब कि वास्तव में उनका उद्देश्य केवल अपनी कुर्सी को बचाना था जिस की सजा देश की जनता ने उन्हें दे दी है इस लिए मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि संविधान में कोई रद्दो-बदल या परिवर्तन किया जाये ।

हिटलर भी तानाशाह था, लेकिन इस के बावजूद उस में एक गुण था । उस ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि मुझे मान्य नहीं है कि देश में मेरे नाम से कोई सम्पत्ति हो लेकिन यदि जर्मन राष्ट्र मे कभी भी मेरे नाम से कोई सम्पत्ति है, तो वह जर्मन राष्ट्र की सम्पत्ति है । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हिटलर की नकल की, लेकिन हिटलर मे जो गुण था, वह उन में नहीं था, क्योंकि अपने बेटे के लिए और अपनी सत्ता को बचाने के लिए जो कुकर्म उन्होंने किया और जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया, वह देश और दुनिया के सामने विद्यमान है । इसलिए मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि संविधान की जो मर्यादा है जो उस में भावनाएं हैं उन को देखते हुए उस को ज्यों का त्यों रहने दीजिए । साथ ही जो संविधान के साथ अन्याय किया गया, जुल्म किया गया, जो गलत ढंग से उसका अनुपालन किया गया, उसमें परिवर्तन लाया गया, आप जो आठ जनता पार्टी के रूप में सत्ता में आए हैं आप से हिन्दुस्तान की 60 करोड़ जनता यह उम्मीद नहीं रखती है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे और आगे आने वाले दूसरे लोग भी जब कभी सत्ता परिवर्तन इस देश में होगा तो उन के लिए भी यह एक हृत् तक हिदायत के रूप में है कि यह गांधी का देश है, यह सुभाष चन्द्र बोस का देश है, यह रबीन्द्र नाथ टैगोर का देश है, इस देश में कभी भी तानाशाही नहीं चल सकती है, नहीं पनप सकती है । यह

सबक लोगों को मिल गया है और चाहे चल कर सस्ता में घाने वाले लोगों के लिए भी यह सबक रहेगा । इसलिए आप इसमें परिवर्तन क्यों चाहते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि इसकी मर्यादा और इसकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए आप इसमें कोई परिवर्तन मत कीजिए और इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए ।

इन्ही भावनाओं के साथ मैं घोषणा करता हूँ कि जो हमारी सरकार है वह संविधान की समुचित मर्यादा को कायम रखेगी ।

**SHRI C. N. VISVANATHAN** (Tiruppattur): Sir, I am rising to explain the policies adopted by my party, i.e. AIADMK, during the emergency. Many people in the House may think that we supported the emergency and Mrs. Indira Gandhi. But actually if one reads the speeches of the members of our party in this House during the emergency, when the forty-second amendment Bill and other Bills were discussed one will understand our policies. Actually, Mr. Maya Thevar opposed the Advocates Amendment Bill. Our party also opposed the dilution of fundamental rights and we said that fundamental rights should not be changed. When emergency was declared, the former Chief Minister of Tamilnadu, Mr. Karunanidhi, actually used the emergency weapon against our party and arrested one J.P.R. without any cause and kept him in jail for 14 months. When M.G.R. became Chief Minister and when he came to Delhi to meet the Central Ministers, at the Delhi airport, the question was put to him as to why he is supporting the Janata Government now and why he was silent during the emergency. The reply he gave was, "This government has given the liberty to speak and write. So, we are supporting the Janata Government. But during the emergency,

there were no fundamental rights and the right to speak or write was banned."

At the same, we are not fully opposed to the emergency because there are some good things. The good things may be less than the evils. In north India, so many leaders who have worked for the nation suffered. But in the south, that thing did not happen. We did not know much about the evils of the emergency period. At the same time, we have to see the good things of the emergency. Trains were running punctually. Offices functioned properly. Blackmarketeers were arrested. Smugglers who deprived the country of valuable foreign exchange were arrested. We should not forget these things. With the present laws, we cannot arrest the smugglers who are taking advantage of the loopholes of the law and escaping. I am an advocate and I know how the loopholes in the law are coming to the help of the smugglers, tax-evaders and other economic offenders. Rich people are evading payment of thousands of crores of income-tax and other taxes due to the exchequer. The Constitution is indirectly helping those who are taking the law into their own hands and evading taxes. Even now we cannot collect thousands of crores of taxes. Because of the constitutional liberties, because of the Fundamental Rights and because of the writs in the courts they have taken advantage of the loopholes and they are escaping. We must do something definitely in this regard. There should be some amendment of the Constitution whereby nobody should escape through the constitutional loopholes.

I may humbly submit that I also support the Bill moved by Mr. H. V. Kamath. This evil should not be continued or repeated in India by anybody, not only by Mrs. Indira Gandhi, but by anybody. Nobody should be allowed to perpetrate this evil and cut out the

[Shri C. N. Visvanathan]

Fundamental Rights at any cost. So the Constitution must be changed accordingly.

श्री दुर्गा चन्द्र (कांगड़ा) : सभापति महोदय, इमजेंसी के मुतालिक भारत की जनता को पिछले 19 महीनों में जो अनुभव हुआ है उससे जनता पार्टी सरकार को लाभ उठाना चाहिए। एक्सटर्नल इमजेंसी की जो बात कही जाती है, वह तो दुष्मन का कभी हमला हो या जिसकी सभावना हो उसको रोकने के लिए सरकार ऐसा इंतजाम करना चाहे तो कर सकती है लेकिन कामत साहब ने जो बिल रखा है उसमें लिखा है "ग्रान्ड इनसरेक्शन"—प्रगर इस देश में ग्रान्ड रेवेलियन हो तब इंटर्नल इमजेंसी घोषित की जानी चाहिए, इस प्रकार का प्राविधान संविधान में रखने की बात कही गई है लेकिन मैं समझता हूँ पिछले तीस साल का जो हमारा अनुभव रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का जिसमें कांग्रेस की हुकूमत रही उसमें ऐसे वाक्यात प्राये जैसे बिहार और तेलंगाना में वायलेंट मूवमेन्ट्स हुए तो क्या उस वक्त इमजेंसी घोषित की गई थी? उस वक्त इमजेंसी नहीं लगाई गई थी। जो कामना ला आफ दि सचर्ड थे उनके भातहत ही उन मूवमेन्ट्स की अरेस्ट किया गया और लोगों का जो विश्वास था उसको पुरश्चमन हलात पर रखा गया मैं समझता हूँ इस प्रकार का इंटर्नल इमजेंसी का प्राविधान भी रखना हमारे लोकतंत्र पर और हमारी डिमोक्रेसी पर एक दाग सा रहेगा क्योंकि उसका मतलब यह होगा कि हम लोगों को अपने ऊपर

विश्वास नहीं है। इस देश के लोगों को यह अघिकार है कि प्रगर कोई सरकार ठीक इंतजाम नहीं कर सकती तो उसको पांच साल के बाद बदल दिया जाये। जब लोगों के पास इतनी बड़ी ताकत है तो सरकार को खुद ताकत रिटेन करने की क्या जरूरत है? अफसोस तो इस बात का है कि हमारे देश में जो सियासी पार्टियाँ हैं उनको जिस तरीके से लोगों को पुरश्चमन तरीके से प्रीच करना चाहिए और डिमोक्रेसी की बैल्यूज का आभास, कराना चाहिए वह काम तो कम करती हैं, लोगों के मतलों को हच करने के लिए वायलेंट पर तैयार करने की कोशिश ज्यादा करती हैं।

अभी परलो तरफ से हमारे भाई ने कहा कि जनता पार्टी ने यह वायदा किया था, वह वायदा किया था, कहा था कि इमजेंसी की आर्टिकल 352 को हम संविधान से निकाल देंगे लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इस किरम की चीज इस देश में लायी गई थी, जब इसका नाजायज इस्तेमाल किया गया था, कितने ही लोग जेलों में ही मर गये और कितने डिसेबिल हो गए, हजारों घर बरबाद हो गए तब वे कहाँ पर सोये हुए थे जो आज यहाँ पर हीरो बन रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, जिस समय इंटर्नल इमजेंसी लायी की गई, लोगों पर प्रतिबन्ध लगाये गये और संविधान की अगिजियाँ उड़ाई गई, फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया उस वक्त वे सोये हुए थे और आज कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की जरूरत है। नुजीम कोर्ट में गोलकनाथ केस में जो फैसला हुआ था उसमें बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती लेकिन

बाद में उसको भी बदल दिया गया। मैं समझता हूँ यहाँ की जनता को सेफगार्ड चाहिए ताकि कभी हुकूमत में कोई ऐसा एलिमेण्ट न आ जाये जो डिमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों की सुप्रीमसी को खत्म कर दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंटर्नल इमर्जेंसी की भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक्सटर्नल इमर्जेंसी की प्राविजन ही रहनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कानून हैं, जिनके मातहत हम डकैती और क्रतल करने वालों को सजा दे सकते हैं। ऐसे घाईबरी कानून हमारे पास हैं लेकिन अगर उनसे काम नहीं चलता है तो कोई दूसरा इस तरह का कानून पास कर सकते हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि इण्टरनल इमर्जेंसी लगाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

SHRI P. K. DEO: I beg to move:

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 352) be adjourned."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 352) be adjourned."

*The motion was adopted.*

15.46 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)  
BILL

(Amendment of article 124)  
by Shri P. K. Deo.

MR. CHAIRMAN: We will now take up Mr. P. K. Deo's Bill.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Sir, if you go through the Statement of Objects and Reasons, you will be convinced that no persuasion is required to accept this simple Bill. The Statement of Objects and Reasons says:

"The Constitution of India does not lay down any procedure for the appointment of the Chief Justice of the Supreme Court, though the Constitution is clear regarding the procedure of the appointment of other Judges of the Supreme Court. Any citizen of India who has been a Judge of a High Court or of two or more such courts for five years or has been an Advocate of a High Court or of two or more such courts for at least ten years and is considered by the President as a distinguished jurist is eligible for such appointment. The appointment of the Chief Justice of the Supreme Court is within the discretionary powers of the President who acts on the advice of the Council of Ministers. It is, therefore, high time that the procedure for the appointment of the Chief Justice of the Supreme Court is laid down."

You will agree with me, Sir, that there should be some guideline for the appointment of the Chief Justice of Supreme Court. I have said that the guideline should be in consonance with the practice that has been followed, and has been well accepted in this country. If you analyze the appointment of the Chief Justice of the Supreme Court, you will find that there have been only two occasions when there was departure from this established practice. The first was when Justice Gajendragadkar became the Chief Justice, superseding Justice Imam, because unfortunately, the latter was incapacitated. He simply could not function as a Judge,